तूफान का कहर : यात्री बस पलटी, 16 लोग घायल

नवभारत न्यूज

श्योपुर, 7 जून। श्योपुर जिले के बड़ौदा क्षेत्र में आए एक भीषण तूफान के कारण एक बड़ा सड़क हादसा हो गया है। बड़ौदा से रतोदन की ओर जा रही एक यात्री बस अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। इस दर्दनाक हादसे में करीब 16 यात्रियों के घायल होने की खबर है।

कोई जनहानि नहीं, बाल-बाल बचे यात्री: राहत की बात यह रही कि इतनी बड़ी दुर्घटना के बावजूद हादसे में किसी भी व्यक्ति की जान नहीं गई है। सभी यात्री सुरक्षित हैं और घायलों का इलाज चल रहा है।



मौके पर पहुंचे अधिकारी और पुलिस : घटना की सूचना मिलते ही राजस्व निरीक्षक दिव्यराज धाकड़ तुरंत मौके पर पहुंचे। उनकी मौजूदगी में सभी घायल यात्रियों को रेस्क्यू कर तत्काल उपचार के लिए नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है।

हादसे का स्थान यह दुर्घटना महाराजपुरा रोड पर घटित हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ौदा थाना पुलिस भी तुरंत मौके पर पहुंच चुकी है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है।

ट्रेन में नाबालिग से मारपीट, तीन आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज

परासिया. आमला-परासिया पैसेंजर ट्रेन में एक नाबालिग यात्री के साथ मारपीट का मामला सामने आया है. घटना शुक्रवार को उस समय हुई जब ट्रेन में यात्रा के दौरान बैग टकराने को लेकर दो यात्रियों के बीच कहासुनी हो गई, जो बाद में विवाद में बदल गई. चांदामेटा निवासी रुपेश वर्मा आमला से परासिया तक ट्रेन क्रमांक 61125 में यात्रा कर रहा था. इसी ट्रेन में जुन्नारदेव से परासिया तक यात्रा कर रहे 16 वर्षीय मोहम्मद अयान रजा का बैग रुपेश वर्मा से टकरा गया, जिसके बाद दोनों के बीच कहासुनी हो गई. बताया गया कि शाम करीब 5:23 बजे ट्रेन के परासिया स्टेशन पहुंचने पर रुपेश वर्मा को लेने आए उसके मित्र शिवम मसराम और अजय कुमार धुर्वे भी मौके पर पहुंच गए.

फार्मर आईडी के लिए किसानों को करें जागरूक



नवभारत न्यूज

श्योपुर, 7 जून। सांसद शिवमंगल सिंह तोमर ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित बैठक के दौरान कहा कि फार्मर आईडी के लिए किसानों को जागरूक किया जायें तथा अभियान के तहत शत प्रतिशत किसानों की फार्मर रजिस्ट्री का कार्य पूर्ण किया जायें। उन्होंने कहा कि इसके प्रति किसानों को जागरूक किया जायें तथा फार्मर आईडी बनाने के लिए गठित दल की गांव में पहुंचने से पूर्व सूचना का प्रचार-प्रसार कराया जायें। वे आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में गत दिनों संपन्न हुई दिशा की बैठक में लिये गये निर्णयों के क्रियान्वयन एवं प्रगति के संबंध में अधिकारियों से अनौपचारिक चर्चा कर रहे थे।

सांसद श्री तोमर ने कहा कि जिले में 3 जून से 20 जून तक फार्मर आईडी बनाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है, इस अभियान के दौरान सभी किसानों के फार्मर आईडी बनाने का कार्य पूर्ण किय जायें, साथ ही ई-विकास प्रणाली के संबंध में भी किसानों को जानकारी प्रदान की जायें। इस दौरान एसएलआर कुलदीप बोहरे ने बताया कि जिले में अधिकतर किसानों की फार्मर आईडी का कार्य पूर्ण किया जा चुका है, जिन किसानों के दो सर्वे में नाम है, उन सबको एकजाई करने की कार्यवाही भी अभियान के तहत की जा रही है। उप संचालक कृषि श्री जीके पचौरिया ने बताया कि वर्तमान में कुल 13097.145 मै.टन उर्वरक उपलब्ध है। केन्द्र एवं प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के शेष पात्र हितग्राहियों को लाभ प्रदान किये जाने के उद्देश्य से विकासखण्ड मुख्यालयों पर आयोजित किये जा रहे तीन दिवसीय शिविरों का प्रचार-प्रसार किया जायें तथा इन शिविरों में ऐसे पात्र हितग्राही जो योजनाओं के लाभ से शेष है, उनका पंजीयन कर लाभ प्रदान करने की कार्यवाही की जायें।

ककरदा पंचायत में अनियमितताओं का आरोप

कुणाल जादौन

कराहल (श्योपुर)। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के आदिवासी बाहुल्य विकासखंड कराहल की ग्राम पंचायत कलमी ककरदा इन दिनों भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं का सबसे बड़ा केंद्र बनती जा रही है। पहले बिना सील-साइन के 85 हजार रुपये के फर्जी बाउचर का मामला थमा भी नहीं था कि अब सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ाता हुआ एक और बड़ा कारनामा सामने आया है। पंचायत रिकॉर्ड में मोरम (सड़क निर्माण-भराव सामग्री) खरीदी के नाम पर एक स्थानीय फर्म का ?99,000 (निन्यानवे हजार रुपये) का एक ऐसा संदिग्ध बिल लगाया गया है, जिसे देखकर जिले के वरिष्ठ अधिकारी भी हैरान हैं।

विकासखंड कराहल के जागरूक ग्रामीणों द्वारा जुटाए गए दस्तावेजों के अनुसार, ग्राम पंचायत कलमी ककरदा में फॉर्म का एक बिल लगाया गया है। इस बिल की बारीकियां खुद ब खुद भ्रष्टाचार की कहानी बयां कर रही हैं। बिल क्रमांक: 147 बिल की तारीख: गायब (बिल पर कोई तारीख ही दर्ज नहीं की गई है) समग्री: मोरम सप्लाई कुल भुगतान राशि: शासन के नियमों के अनुसार यह बिल सही है या पूरी तरह गलत

1 लाख की सीमा से ठीक 1,000 कम क्यों? : पंचायती राज और सरकारी ऑडिट के नियमों में एक बड़ा पेंच है। आमतौर पर 1,00,000 (एक लाख रुपये) या उससे अधिक के भुगतानों पर जिला स्तर या तकनीकी अधिकारियों की विशेष स्क्रूटनी (कड़ी जांच) और कोटेशन/टेंडर की प्रक्रियाएं कड़क हो जाती हैं। जांच से बचने के लिए भ्रष्टाचार करने वाले अक्सर ?99,000 जैसी राशि चुनते हैं, ताकि बिल एक लाख की सीमा से ठीक नीचे रहे और ऊपरी अधिकारियों की नजरों में न आए। कलमी ककरदा पंचायत में ठीक यही फॉर्मूला अपनाया गया है।

सरपंच-सचिव और रोजगार सहायक की भूमिका संदिग्ध, कलेक्टर से शिकायत की तैयारी : ग्रामीणों का सीधा आरोप है कि ग्राम पंचायत कलमी ककरदा के जिम्मेदार अधिकारी-कर्मचारी (सचिव, रोजगार सहायक और सरपंच) मिलकर सरकारी बजट को ठिकाने लगा रहे हैं। बिना तारीख और फर्जी टैक्स नंबर वाले इस बिल को पंचायत के रिकॉर्ड में शामिल करना और इसके आधार पर भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ाना बिना मिलीभगत के संभव नहीं है।

मोरम और खनिज रॉयल्टी का नियम

शासन के नियमानुसार यदि पंचायत कोई मोरम, गिट्टी या रेत खरीदती है, तो बिल के साथ खनिज विभाग की रॉयल्टी रसीद लगाना अनिवार्य है। बिना वैध रॉयल्टी के मोरम का अवैध खनन और परिवहन माना जाता है। इस 99,000 के बिल में किसी रॉयल्टी का कोई अता-पता नहीं है। 10,000 से ऊपर नगद/चेक भुगतान पर रोक- यदि यह राशि बिना वेंडर (फर्म) के वैध चालू खाते में सीधे डिजिटल ट्रांसफर किए बिना निकाली गई है, तो यह सीधे तौर पर वित्तीय गबन का मामला बनता है।

कलेक्टर से शिकायतों के बाद पटवारी निलंबित

सीधी. कलेक्टर विकास मिश्रा के राजस्व निरीक्षक मंडल खड्डी के क्षेत्र भ्रमण के दौरान ग्रामीणों द्वारा प्राप्त शिकायतों एवं जांच प्रतिवेदन के आधार पर खड्डी खुर्द एवं खड्डी कला हल्के के पटवारी बृजेश कुमार प्रजापति को निलंबित कर दिया गया है. क्षेत्र भ्रमण के दौरान ग्रामीणों ने नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन सहित विभिन्न राजस्व प्रकरणों के निराकरण में अनावश्यक विलंब तथा कार्य के लिए अवैध राशि की मांग किए जाने संबंधी शिकायतें की थीं. कलेक्टर के निर्देश पर कराई गई. . नायब तहसीलदार हनुमानगढ़ द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के परीक्षण के उपरांत शासकीय कार्यों में लापरवाही एवं अनुशासनहीनता पाए जाने पर उपखंड अधिकारी (राजस्व) रामपुर नैकिन विकास आनंद ने मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत पटवारी बृजेश कुमार प्रजापति को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं. निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय तहसील कार्यालय रामपुर नैकिन निर्धारित किया गया है.

सड़क निर्माण के तय मापदंडों में भारी लीपापोती

नवभारत न्यूज

श्योपुर/गोरस, 7 जून। मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा को जोड़ने वाला अत्यंत महत्वपूर्ण नेशनल हाईवे 552 (विस्तारित) का पाली-श्योपुर-गोरस खंड इन दिनों भ्रष्टाचार, कछुआ चाल और तकनीकी गड़बड़ियों के गंभीर आरोपों से घिरा हुआ है। जनता की सहूलियत के नाम पर स्वीकृत करोड़ों रुपयों का यह प्रोजेक्ट

नेशनल हाईवे एनएच 552 निर्माण में बड़ा खेल

विभागीय अधिकारियों (एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सब इंजीनियर) और ठेका कंपनी की साठगांठ के चलते विवादों की भेंट चढ़ता नजर आ रहा है। स्थानीय जनता और जागरूक नागरिकों का सीधा आरोप है कि सड़क निर्माण के तय मापदंडों में भारी लीपापोती की गई है।

इस नेशनल हाईवे का निर्माण तीन अलग-अलग चरणों में स्वीकृत हुआ था, जिसमें से पाली (चंबल पुल) से लेकर श्योपुर-गोरस तक का हिस्सा पहला चरण है। पुराना और नया एस्टीमेट- शुरुआत में इस रूट को लेकर शुरुआती डीपीआर तैयार की गई थी। इसके बाद केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने पाली-श्योपुर-गोरस खंड (कुल लंबाई 48 किलोमीटर) के लिए ?483 करोड़ 21 लाख की अंतिम वित्तीय मंजूरी दी थी।

इसके ठीक आगे वाले खंड गोरस से श्यामपुर (63.40 किमी) के लिए 355 करोड़ से ?417 करोड़ का अलग एस्टीमेट स्वीकृत है। इस प्रकार केवल पाली से गोरस के बीच की 48 किलोमीटर की सड़क के लिए प्रति किलोमीटर लगभग ?10 करोड़ का भारी-भरकम बजट आवंटित है।

शासन के नियमों और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के तय मापदंडों के अनुसार इस हाईवे का स्वरूप इस प्रकार होना था। हाईवे की कुल चौड़ाई 15 मीटर तय की गई थी। सड़क के ठीक बीच में 1 मीटर चौड़ा पक्का डिवाइडर बनना अनिवार्य था।

मुख्य सड़क डिवाइडर के दोनों ओर 5-5 मीटर की चमचमाती डामर और सीसी (सीमेंट कंक्रीट) की मुख्य सड़कें बननी थीं। मुख्य सड़क के दोनों किनारों पर 2-2 मीटर के पक्के शोल्डर (अतिरिक्त पट्टी) बनने थे, ताकि वाहन खराब होने पर किनारे खड़े हो सकें।

विद्युत पोल शिफ्टिंग और पेपर ब्लॉक- घनी आबादी और कस्बों (जैसे गोरस और पाली) में सड़क चौड़ीकरण के दायरे में आने वाले पुराने बिजली के पोल को हटाकर किनारे पर नवीन विद्युत पोल शिफ्टिंग की जानी थी। साथ ही पैदल यात्रियों और बाजार क्षेत्र के लिए शानदार पेपर ब्लॉक और सुव्यवस्थित लाइटिंग (स्ट्रीट लाइट) की व्यवस्था की जानी थी। कागजों पर यह प्रोजेक्ट जितना शानदार दिखता है, धरातल पर उतनी ही बदहाली और अनियमितता के आरोप लग रहे हैं। इस रोड से श्योपुर और राजस्थान के बीच व्यापार को गति मिलनी थी, ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलनी थी और 7.05 किलोमीटर के श्योपुर बायपास व अन्य कस्बों के बायपास से जनता का समय बचना था। लेकिन निर्माण में देरी और घटिया काम के चलते धूल, गड्ढे और हादसों के अलावा जनता को कुछ नहीं मिल रहा है।

डिवाइडर और पोल शिफ्टिंग में लापरवाही

स्थानीय निवासियों के अनुसार, गोरस-पाली रोड पर कई जगहों पर पुराने बिजली के खंभों को ठीक से शिफ्ट नहीं किया गया, जिससे वे हादसों को न्योता दे रहे हैं। जो नया डिवाइडर और पोल शिफ्टिंग का काम हुआ है, उसमें घटिया सामग्री और पुरानी डिजाइन का इस्तेमाल कर महज औपचारिकता पूरी की गई है। डामरीकरण की घटिया गुणवत्ता - पहली बारिश में ही सड़क के उखड़ने और घटिया डामरीकरण की शिकायतें आ रही हैं। तय नियमों के अनुसार जितनी मोटी डामर की परत और सीसी रोड की मोटाई होनी चाहिए थी, उसमें भारी कटौती कर ठेकेदार ने लीपापोती कर दी है।

ओंकारेश्वर में अतिक्रमण हटाने के नोटिस पर सियासत तेज

ओंकारेश्वर/खंडवा. सिंहस्थ-2028 की तैयारियों के तहत ओंकारेश्वर में प्रस्तावित अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को लेकर विरोध शुरू हो गया है.

नगर परिषद द्वारा वार्ड क्रमांक 15 में निवासरत कुछ परिवारों को 24 घंटे के भीतर शासकीय भूमि खाली करने का नोटिस जारी किए जाने के बाद कांग्रेस ने इस पर आपत्ति दर्ज कराई है और प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की मांग उठाई है. प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर परिषद ओंकारेश्वर के राजस्व विभाग ने 5 जून को वार्ड क्रमांक 15, डैम रोड एवं नहर क्षेत्र के कुछ निवासियों को नोटिस जारी कर बताया है कि आगामी सिंहस्थ-2028 के मद्देनजर श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया जाना है. नोटिस में 24 घंटे के भीतर स्वयं अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए हैं, अन्यथा प्रशासनिक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है. मामले को लेकर जिला कांग्रेस अध्यक्ष उत्तमपाल सिंह ने प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं.

बीड़ी श्रमिकों के बच्चों को मिलेगी 25 हजार तक छात्रवृत्ति

नवभारत न्यूज

श्योपुर, 7 जून। बीड़ी श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए सरकार द्वारा वित्तीय सहायता (छात्रवृत्ति) योजना संचालित है। जिसके तहत शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस योजना के अंतर्गत कक्षा 1 से उच्च शिक्षा तक अध्ययनरत पात्र छात्र-छात्राओं को 1 हजार रुपये से 25 हजार रुपये तक की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।

श्रम कल्याण विभाग द्वारा संचालित इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र छात्र-छात्राओं को नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन प्रक्रिया 1 जून 2026 से प्रारंभ हो चुकी है। प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2026 तथा पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए 31 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई है। छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने से पूर्व ओटीआर एवं फेस ऑथेंटिकेशन की प्रक्रिया पूर्ण करना अनिवार्य है। योजना की पात्रता, नियम एवं अन्य आवश्यक जानकारी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर उपलब्ध है। आवेदकों को आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज स्पष्ट एवं पठनीय रूप में स्कैन कर अपलोड करना होगा। आवेदन जमा करने के बाद छात्र-छात्राएं अपने विद्यालय अथवा महाविद्यालय से संपर्क कर यह सुनिश्चित करें कि उनका आवेदन पोर्टल पर समय-सीमा में सत्यापित हो जाए। योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए जबलपुर मुख्यालय के दूरभाष क्रमांक 0761-4039511 एवं 0761-4039510 पर संपर्क किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त ई-मेल आईडी तथा पर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। साथ ही मध्यप्रदेश परिक्षेत्र में संचालित निकटतम औषधालयों तथा केंद्रीय चिकित्सालय, सागर से भी योजना संबंधी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।



युवा कांग्रेस ने किया प्रदर्शन

आलीराजपुर. जिले में रविवार को युवक कांग्रेस ने बेरोजगारी, नीट पेपर लीक, भर्ती घोटालों और बढ़ती महंगाई के मुद्दों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया. प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर कार्यालय का घेराव कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. प्रदर्शन का नेतृत्व उदय भानु चिब, राष्ट्रीय महासचिव एवं मध्यप्रदेश प्रभारी सीबी सिंह चौहान और जिला अध्यक्ष पुष्पराज रावत पटेल ने किया.

एसएनजी आर्ट एंड क्राफ्ट समर कैंप का समापन

नवभारत न्यूज

ग्वालियर, 7 जून। एसएनजी आर्ट एंड क्राफ्ट द्वारा डीबी सिटी में आयोजित समर कैंप का समापन समारोह उत्साहपूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा की जिला कोषाध्यक्ष एवं वैश्य महासम्मेलन की संभागीय अध्यक्ष स्वाति अग्रवाल उपस्थित रहीं। इस मौके पर बड़ी संख्या में



अभिभावक भी मौजूद थे। समापन अवसर पर बच्चों द्वारा तैयार किए गए आर्ट एवं क्राफ्ट प्रोजेक्ट्स की आकर्षक प्रदर्शनी लगाई गई, जिसे सभी ने खूब सराहा। साथ ही बच्चों ने मनमोहक नृत्य प्रस्तुतियां देकर समां बांध दिया। कैंप की संयोजिका शिल्पी गोयल ने बताया कि शिविर में बच्चों को स्केटिंग,ड्रॉइंग व कैलिग्राफी तथा मेहंदी, डांस व आर्ट-क्राफ्ट का प्रशिक्षण दिया गया।

कंस वध, रुक्मिणी विवाह प्रसंग पर झूमे श्रद्धालु

नवभारत न्यूज

ग्वालियर, 7 जून। श्री दादाजी धाम धर्मपुरी मंदिर में पुरुषोत्तम मास के उपलक्ष्य में आयोजित श्रीमद्भागवत

श्री दादाजी धाम में भागवत कथा का समापन

कथा के सातवें दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। कथा व्यास जगद्गुरु स्वामी रामेश्वरानंद ने श्रीकृष्ण की मथुरा लीला, कुब्जा उद्धार, कंस वध, रुक्मिणी विवाह और पांडवों के राजसूय यज्ञ प्रसंग का आध्यात्मिक रहस्यों के साथ भावपूर्ण वर्णन किया।

रामेश्वरानंद ने आध्यात्मिक संदेश देते हुए कहा कि कुब्जा का सीधा होना विकृत विचारों के शुद्ध होने का प्रतीक है, वहीं कंस वध हमारे भीतर के क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार की समाप्ति का संदेश देता है। रुक्मिणी विवाह प्रसंग पर 'आओ मेरी साखियों मुझे मेहंदी लगा दो...' भजन पर श्रद्धालु झूम उठे। उन्होंने बताया कि राजसूय यज्ञ में श्रीकृष्ण की अग्रपूजा यह सिखाती है कि जीवन के हर कार्य में ईश्वर को सर्वोच्च स्थान देना ही सफलता का मूल मंत्र है। मुख्य यजमान राधाकृष्ण कारड़ा, संगीता कारड़ा, संदीप कारड़ा और श्याम कारड़ा ने सपरिवार महाआरती कर श्रद्धालुओं में प्रसाद वितरण किया।

मठों व ऐतिहासिक स्थलों का किया भ्रमण

नवभारत न्यूज

ग्वालियर, 7 जून। जीवाजी विश्वविद्यालय के प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व अध्ययनशाला के विभागाध्यक्ष डॉ. शांतिदेव सिसोदिया ने कहा है कि इतिहास लेखन के लिए

अभिलेखागार और क्षेत्रीय अध्ययन के बिना प्रामाणिक इतिहास लेखन संभव नहीं : डॉ. शांतिदेव

अभिलेखीय स्रोत, क्षेत्रीय सर्वेक्षण और प्रत्यक्ष अध्ययन ही सबसे विश्वसनीय आधार हैं। गुणवत्तापूर्ण शोध के लिए शोधार्थियों को केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित न रहकर मूल स्रोतों के वैज्ञानिक



विश्लेषण और फील्ड स्टडी पर ध्यान देना चाहिए।

डॉ. सिसोदिया जीवाजी विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश और ठाकुर रामसिंह इतिहास शोध संस्थान के बीच हुए एमओयू के तहत आयोजित त्रिदिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला को मुख्य वक्ता के रूप में संबोधित किया । सामाजिक विज्ञान में सिद्धांत और व्यवहार विषय पर आयोजित इस कार्यशाला में देशभर के विद्वानों और शोधार्थियों ने हिस्सा लिया।

कार्यशाला में केंद्रीय विवि हिमाचल प्रदेश के इतिहास विभागाध्यक्ष डॉ. जगदीश प्रसाद और डॉ. राघवेंद्र यादव ने भी शोध में संस्थानों के आपसी सहयोग को बढ़ाने पर बल दिया।

आलमपुर को दतिया में शामिल करने की मांग

भिंड. लहार तहसील के आलमपुर और उसके थाना क्षेत्र के सभी गांवों को भिंड जिले से अलग कर दतिया जिले में शामिल करने के लिए पूर्व जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारी रहे लोगों ने भोपाल पहुंचकर मध्यप्रदेश प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग को ज्ञापन सौंपा. यह ज्ञापन पूर्व राज्यमंत्री रमाशंकर चौधरी, सेवढ़ा के पूर्व विधायक रामदयाल प्रभाकर और सेवानिवृत्त कमिश्नर महेशचंद्र चौधरी ने आयोग के सचिव एस.एन. मिश्रा को सौंपा. ज्ञापन में कहा गया है कि आलमपुर क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा रहा है. पूर्व में यह बुंदेला शासन और बाद में होल्कर स्टेट की तहसील के रूप में स्थापित था।

संविदा स्वास्थ्यकर्मियों ने किया सद्बुद्धि यज्ञ

नवभारत न्यूज

ग्वालियर, 7 जून। मध्य प्रदेश संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के आह्वान पर संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल रविवार को छठे दिन भी जारी रही। अपनी मांगों को लेकर अड़े कर्मचारियों ने रविवार को फूलबाग स्थित धरना स्थल पर सरकार को जगाने के लिए सद्बुद्धि यज्ञकिया और आहुतियां दीं।

धरना प्रदर्शन में दो सैकड़ा से अधिक संविदा कर्मचारी शामिल हुए। खास बात यह है कि भीषण गर्मी के बावजूद महिला कर्मचारी अपने छोटे-छोटे बच्चों को गोद में लेकर पंडाल में डटी हुई हैं। कर्मचारियों ने रोष जताते हुए कहा



कि आंदोलन के छह दिन बीत जाने के बाद भी शासन या प्रशासन का कोई अधिकारी या जनप्रतिनिधि उनकी सुध लेने नहीं पहुंचा है। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के अध्यक्ष धर्मवीर शुक्ला ने स्पष्ट किया कि उनकी कोई नई मांग नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही उनकी मांगों पर अमल नहीं हुआ, तो प्रदेशभर के संविदा कर्मचारी भोपाल कूच कर मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेंगे। वर्ष 2023 में आयोजित महापंचायत के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने संविदा नीति जारी की थी, लेकिन आज तक उसका पूरी तरह पालन नहीं हो सका है। इस दौरान धरना स्थल पर इमरान खान, पुरेंद्र राजपूत, सोनू राठौर, महेश कुशवाहा, सत्यनारायण प्रजापति, प्रशांत सक्सेना, संदीप गुप्ता, संजय सहित बड़ी संख्या में संविदा कर्मचारी उपस्थित रहे।